भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-224
सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

नौकरियां खोना

224. श्री एच॰ वसंतकुमारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ महीनों में बेरोजगारी की दर 8.5 प्रतिशत से अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौकरी खोने के ज्यादा मामले ग्रामीण आबादी से संबंधित हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि लगभग 40 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 6.1% थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। 2011-12 एवं 2017-18 के दौरान देश में सभी आयु के ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया हैः

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
2017-18* (पीएलएफएस)	**35.0**	**33.9**	**34.7**
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	**39.9**	**35.5**	**38.6**

*(टिप्पणीः *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

(घ एवं ङ) सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अप्रैल, 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क से ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) दृष्टिकोण के अनुसार सभी आयु के व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दर के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगार दर (% में)
1.	आंध्र प्रदेश	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.9
3.	असम	8.1
4.	बिहार	7.2
5.	छत्तीसगढ़	3.3
6.	दिल्ली	9.7
7.	गोवा	13.9
8.	गुजरात	4.8
9.	हरियाणा	8.6
10.	हिमाचल प्रदेश	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	5.3
12.	झारखंड	7.7
13.	कर्नाटक	4.8
14.	केरल	11.4
15.	मध्य प्रदेश	4.5
16.	महाराष्ट्र	4.9
17.	मणिपुर	11.6
18.	मेघालय	1.5
19.	मिजोरम	10.1
20.	नागालैंड	21.4
21.	ओडिशा	7.1
22.	पंजाब	7.8
23.	राजस्थान	5.0
24.	सिक्किम	3.5
25.	तमिलनाडु	7.6
26.	तेलंगाना	7.6
27.	त्रिपुरा	6.8
28.	उत्तराखंड	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	6.4
30.	पश्चिम बंगाल	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8
32.	चंडीगढ़	9.0
33.	दादरा और नगर	0.4
34.	दमन और दीव	3.1
35.	लक्षद्वीप	21.3
36.	पुडुचेरी	10.3
	अखिल भारत	6.1

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय